

उत्तर प्रदेश के एनसीआर ज़िलों में पटाखों पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने [राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र \(NCR\)](#) ज़िलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

मुख्य बिंदु

■ प्रतिबंध के बारे में:

- यह प्रतिबंध **दिल्ली-NCR क्षेत्र** के अंतर्गत आठ ज़िलों पर लागू होता है, जिनमें **मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुज़फ्फरनगर** शामिल हैं।
- प्रतिबंध का क्रयान्वयन **दशहरा और दीपावली** जैसे त्योहारों से पूर्व [सर्वोच्च न्यायालय](#) के निर्देशों के अनुरूप किया गया है, ताकि [NCR में प्रदूषण स्तर को नियंत्रित](#) किया जा सके।
- [पर्यावरण \(संरक्षण\) अधिनियम, 1986](#) की धारा 15 के तहत उल्लंघन करने पर पाँच वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- धारा 15 केंद्र सरकार को किसी भी प्राधिकरण या अधिकारी को पर्यावरण संरक्षण के लिये कार्य करने का निर्देश देने का अधिकार देती है।
- बार-बार अपराध करने पर, अनुपालन होने तक **प्रतिदिन 5,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना** लगाया जाएगा।

■ प्रतिबंध के उद्देश्य:

- वायु प्रदूषण नियंत्रण:** इस प्रतिबंध का उद्देश्य त्योहारों के समय [वायु प्रदूषण](#) में होने वाली वृद्धि, विशेष रूप से पटाखों के उपयोग के कारण होने वाली वृद्धि को रोकना है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण:** इस उपाय का उद्देश्य [सार्वजनिक स्वास्थ्य को वायु प्रदूषण](#) के हानिकारक प्रभावों से बचाना है, विशेष रूप से उच्च प्रदूषण वाले महीनों के दौरान।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

■ पृष्ठभूमि:

- संसद ने इस अधिनियम को [भोपाल गैस त्रासदी](#) के बाद पारित किया, जिसने पर्यावरण और जन-स्वास्थ्य संरक्षण हेतु एक समग्र कानून की तात्कालिक आवश्यकता को रेखांकित किया।

■ संवैधानिक आधार:

- यह अधिनियम **संवधान के अनुच्छेद 253** के अंतर्गत पारित किया गया, जो संसद को [अंतरराष्ट्रीय समझौतों](#) को लागू करने हेतु कानून बनाने का अधिकार देता है। इसे **1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन** में भारत द्वारा की गई अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये लागू किया गया।
- यह अधिनियम केंद्र सरकार को **पर्यावरण प्रदूषण** को रोकने, **नियंत्रित करने** और उसका प्रत्युत्तर देने का अधिकार देता है।
 - इसके अंतर्गत केंद्र सरकार को मानक निर्धारित करने, उत्सर्जन विनियमिति करने, प्रदूषणकारी उद्योगों को बंद करने तथा आवश्यक सेवाओं को नियंत्रित करने का अधिकार है।

■ संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 48A** राज्य को पर्यावरण, वन और वन्य जीवन की रक्षा करने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 51A (g)** प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसे सुधारने का प्रयास करें।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/up-announces-firecracker-ban-in-ncr-districts>

